



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062021-227947
CG-DL-E-28062021-227947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ 7, 1943

No. 177]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

(मामला सं. एडी (ओआई)-07/2021)

विषय: कोरिया गण. जापान और सिंगापुर से इलैक्ट्रोगल्वेनाइज्ड स्टील के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/7/2021-डीजीटीआर.—1. मै. अमेरिकन प्रीकोट स्पेशियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है), ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें कोरिया गण. जापान और सिंगापुर (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित "इलैक्ट्रोगल्वेनाइज्ड स्टील" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक बाधा पहुंची है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद ('पीयूसी') हॉट रोलड या कोल्ड रोलड स्टील के फ्लैट रोलड उत्पाद हैं जिन्हें ज़िंक से निरंतर इलेक्ट्रोलिटिकली प्लेटेड या कोटेड किया जाता है तथा जो मिश्र तत्वों सहित या उसके बिना होते हैं। विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर इलेक्ट्रोगल्वेनाइज्ड स्टील के रूप में जाना जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद अलॉय या गैर अलॉय स्टील हो सकते हैं चाहे प्राइम या गैर प्राइम गुणवत्ता के हों अथवा नहीं। विचाराधीन उत्पाद कॉयल या बिना कॉयल रूप में हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में सभी प्रकार के इलेक्ट्रोगल्वेनाइज्ड स्टील शामिल हैं चाहे कोटेड, पेसीवेटेड, पूर्व-उपचारित, पूर्व पेंटेड, कलर कोटेड, थिन ऑर्गेनिक कोटेड, क्रोमेटेड, फॉस्फेटेड, प्रिंटेड हों अथवा नहीं और नालीदार या प्रोफाइल्ड हों अथवा नहीं और फिंगर प्रिंट रोधी उपचार किया गया हो अथवा नहीं।
5. निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है :
 - i. फ्लैट रोलड स्टील के ऐसे उत्पाद जो एल्युमिनियम या ज़िंक की मिश्र धातु से प्लेटेड या कोटेड हो।
 - ii. फ्लैट रोलड स्टील के ऐसे उत्पाद जो ज़िंक और न्यूनतम 11% के लक्ष्य निकल सहित निकल की मिश्र धातु से प्लेटेड या कोटेड हों।
 - iii. हॉट ट्रिप गेल्वेनाइज्ड फ्लैट रोलड स्टील उत्पाद।
 - iv. टिन मिल फ्लैट रोलड स्टील उत्पाद।
6. विचाराधीन उत्पाद का लक्षित अंतिम प्रयोग जंग से बचाव करना है और इसका मुख्यतः इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के विनिर्माण, आटो अनुप्रयोगों, उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक, फर्नीचर, एचवीएसी, रूफिंग और साइडिंग, सिलिंग ग्रीड, निर्माण, कार्यालय उपकरण आदि में प्रयोग होता है।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7210, 7212, 7225 तथा 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7209 तथा 7211 के अंतर्गत भी किया जाता है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु की गुणवत्ता, उत्पादन और कार्य निष्पादन में कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, कार्य, प्रयोग आदि जैसे सभी संगत मापदंडों में तुलनीय हैं। घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पाद और आयातित उत्पाद का भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।
9. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा अपनाई गई और संबद्ध देशों से निर्यातकों की उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में मै. अमेरिकन प्रीकोट स्पेशियलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है।
11. आवेदक कंपनी ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादित हैं और बाजार में एक नए प्रवेशक ने जुलाई, 2019 में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। इस प्रकार, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनी का उत्पादन भारतीय घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है। अतः

प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

शामिल देश

12. वर्तमान जांच कोरिया गण., जापान और सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में है।

कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने बताया है कि कोरिया गण., जापान और सिंगापुर में उत्पादन लागत और संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत संबंधी सूचना उनके पास नहीं है। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद अनेक एच एस कोडों में वर्गीकृत है और इसलिए आवेदक के पास संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी समुचित तीसरे देश को निर्यात कीमत संबंधी सटीक सूचना नहीं है। अतः संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान कच्ची सामग्री की कीमत और आवेदक द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर तर्कसंगत लाभ सहित परिवर्तन लागत पर विचार करते हुए लगाया गया है।

ख. निर्यात कीमत

14. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों में कतिपय समायोजन करने के बाद सीआईएफ आयात कीमत से कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात की है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, संभलाई प्रभार, कमीशन/व्यापारी का लाभ तथा बैंक प्रभार के लिए समायोजना का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत की तुलना की गई है जो प्रत्येक संबद्ध देश से भारी पाटन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है।
16. पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

17. घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से बाधित कर रहा है। देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा काफी कम है और घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। आवेदक ने दावा किया है कि पीओआई के दौरान उनका वास्तविक कार्य निष्पादन परियोजना रिपोर्ट में प्रत्याशित अनुमानों से कम रहा है। इसके अलावा, पूरी क्षति अवधि तथा पीओआई के दौरान विशेष रूप से जब पीयूसी की आयात कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों से भी कम थी, कीमत कटौती को दर्शाता है और प्रथमदृष्टया आवेदक के खराब कार्य निष्पादन के साथ कथित पाटित आयातों के कारणात्मक संबंध को सिद्ध करता है।
18. पूर्वोक्त से प्राधिकारी प्रथमदृष्टया संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

19. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

20. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि (2017- 2018, 2018- 2019, 2019- 20 और पीओआई होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in तथा dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संबंधित संगत अनुरोध ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों पर प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संबंधित संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

ड. समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in तथा dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी

- साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
 30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
 32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
 33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
 34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
 35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2021

(Case No. AD (OI)-07/2021)

Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Electrogalvanized Steel from Korea RP, Japan and Singapore.

F. No. 6/7/2021-DGTR.—1. M/s. American Precoat Speciality Private Limited (hereinafter referred to as ‘the petitioner’ or ‘the applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Electrogalvanized Steel’ (hereinafter also referred to as the ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) originating in or exported from Korea RP, Japan and Singapore (hereinafter also referred to as the ‘subject countries’).

2. The Applicant has alleged that material retardation is being caused to the establishment of the domestic industry due to dumped imports of subject goods from the subject countries, and has requested for imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject countries.

Product under consideration

3. The product under consideration (‘PUC’) is ‘Flat rolled products of hot rolled or cold rolled steel continuously electrolytically plated or coated with zinc, with or without alloying elements’. The product under consideration is commonly known as Electrogalvanized steel.
4. The product under consideration may be either of alloy or non-alloy steel, whether or not of prime or non-prime quality. The product under consideration may be in coils or not in coils form. The product under consideration includes all types of Electrogalvanized steel whether or not coated, passivated, pre-treated, pre-painted, colour coated, thin organic coated, chromated, phosphated, printed, whether or not corrugated or profiled, and whether or not having anti-fingerprint treatment.
5. The following are excluded from the scope of product under consideration:
- i. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of aluminium and zinc.
 - ii. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of zinc and nickel with nickel being aimed at a minimum 11%.
 - iii. Hot-dip galvanized flat rolled steel products.
 - iv. Tin-mill flat rolled steel products.
6. The intended end use of the product under consideration is for protection from corrosion and is majorly used in the manufacturing of electronic appliances, auto applications, consumer electronics, furniture, HVAC, roofing and siding, ceiling grid, construction, office equipment etc.
7. The product under consideration is classified under HS Codes 7210, 7212, 7225 and 7226 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of the product under consideration have also been made under HS Codes 7209 & 7211 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.

Like Article

8. The applicant has claimed that there are no differences in quality, output and performance of the subject goods imported into India from the subject countries and goods manufactured by the applicant. The subject goods produced by the applicant and those imported from the subject countries are comparable in all relevant parameters such as physical characteristics, manufacturing process,

technology, functions, uses, etc. The domestically manufactured product and the imported product are being used interchangeably by Indian consumers.

9. The applicant has claimed that there are no known major differences in the production process employed by the applicant and the exporters from the subject countries. Therefore, for the purposes of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as “like article” to the product under consideration being imported from the subject countries.

Domestic Industry and Standing

10. The Application has been filed by M/s American Precoat Speciality Private Limited as the domestic industry.
11. The applicant company has claimed that they are the sole producer of subject goods in India and a new entrant in the market having started commercial production of the subject goods in July 2019. Thus, as per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes 100% of Indian domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of Anti-dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti-dumping Rules.

Countries involved

12. The present investigation is in respect of dumping of the product under consideration from Korea RP, Japan and Singapore.

Basis of alleged dumping

a) Normal Value

13. The applicant has submitted that they do not have information regarding the cost of production and domestic selling price for subject goods in Korea RP, Japan & Singapore. The applicant has claimed that product under consideration is classified under multiple HS codes and therefore the applicant does not have accurate information regarding the export price of subject goods from subject countries to an appropriate third country for determination of normal value. Therefore, the normal value for the subject countries has been estimated by considering prices of raw materials and conversion cost with reasonable profit on the basis of best available information provided by the applicant.

b) Export Price

14. The applicant has arrived at the export price at ex-factory level from the CIF import price obtained from DGCI&S import statistics after making certain adjustments. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, inland freight, handling charges, commission/trader profit and bank charges to arrive at export price at ex-factory level.

Dumping Margin

15. The normal value and ex-factory export price have been compared which shows significant dumping from each of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.
16. There is sufficient evidence of significant dumping margins to justify initiation of antidumping investigation.

Evidence of Injury and Causal Link

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry is quite low considering the demand for the product under consideration in the country and considering that the domestic industry commenced commercial

production in July 2019. The applicant has claimed that their actual performance during the POI falls short of the projections expected in project report. Further, the prevalence of price undercutting during the entire injury period and POI especially when import prices of PUC are even lower than the raw material prices, *prima facie* establishes the causality of alleged dumped imports with applicant's subdued performance.

18. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury sufficient to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Initiation of anti-dumping investigation

19. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

20. The period of investigation for the purpose of the present investigation is from 1st January 2020 to 31st December 2020. The injury investigation period for the present investigation will be 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI.

Submission of information

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF / MS Word format and data files are in MS Excel format.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned above.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in within thirty days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limits.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

Submission of information of Non-Confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately:
30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

36. A list of interested parties will be uploaded on DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-cooperation

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority